शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार समूह
मध्यप्रदेश

जब शिक्षक प्रतिदिन घर पर पढ़ा रहे तो फिर क्यों बुलाया जा रहा स्कूल

भोपाल के नए डीपीसी राजेश बाथम को मास्टरों ने बताई समस्याएं

भोपाल(आरएनएन)। अपना घर अपना विद्यालय योजना में ड्यूटी करने के बाद स्कूल बुलाए जाने पर टीचर अधिकारियों के विरोध में खड़े हो गए हैं। शिक्षकों के एक संगठन द्वारा भोपाल के नए डीपीसी राजेश बाथम को एक ज्ञापन सौंपकर पूरी समस्या बताई गई है। शिक्षकों की समस्याओं को लेकर मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ शिक्षा समिति ने नवान्तुक जिला परियोजना समन्वक राजेश बाथम को बिंदुवार समस्या बताएंगे।

समिति के प्रदेश संयोजक अरविंद भूषण श्रीवास्तव ने बाथम को बताया कि हमारा घर हमारा विद्यालय के तहत शिक्षक वर्क फ्राम होम के अलावा प्रतिदिन कम से कम बच्चों के पांच घर जाकर होमवर्क चैक कर रहे हैं। उसके बाद भी शिक्षकों को नियमित शाला बुलाने से शिक्षकों गैरशालाओं में बुलाया जा रहा है। अब शिक्षक घरों पर पढ़ाई या फिर स्कूल में ड्यूटी दे। विभाग को एक निर्णय लेना चाहिए। डीपीसी को बताया गया कि अनेक शिक्षक ऐसे ही जैन का घर स्कूलों से काफी दूरी पर है।

पहली बार अपने घरों से निकलकर बच्चों को उनके आवास पर पढ़ाने जाते हैं। इसके बाद वहां से सीधे उन्हें अधिकारियों के निर्देश का पालन करने के लिए विद्यालय में पहुंचना पड़ रहा है। डबल काम होने से शिक्षकों में रोष व्याप्त है। उन्होंने बताया कि यह कोविड-19 गाइडलाइन का भी उल्लंघन है। डीपीसी ने भरोसा दिया कि शिक्षकों ने जो ज्ञापन दिया है उसे शासन तक पहुंचाया जाएगा।

बाथम ने समझा डीपीसी कार्यालय का कामकाज

करीब 4 माह बाद राजधानी भोपाल को नया डीपीसी मिला है। पदभार ग्रहण करने के बाद नए डीपीसी राजेश बाथम ने कार्यालय में कामकाज की समस्त बारीकी समझी। उन्होंने कार्यालय के समस्त कर्मचारियों की बैठक लेकर लंबित कामों पर चर्चा की। कितने विद्यालयों को नि शुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान होना है। यह जानकारी भी बाथम द्वारा ली गई। जानकारी के अनुसार उन्होंने आगामी दिनों में समस्त विद्यालयों और मदरसों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दिए हैं।

स्कूल खुले न सिलेबस तय, माशिमं ने जारी की परीक्षा आवेदन भरने की तिथि

सामान्य शुल्क के साथ 25 तक भरे जा सकेंगे दसवीं-बारहवीं के परीक्षा फार्म

शहर प्रतिनिधि, भोपाल

प्रदेश में अभी स्कूल खुले नहीं है। सिलेबस भी तय नहीं किया गया, लेकिन दसवीं-बारहवीं के परीक्षा आवेदन भरने की तिथि घोषित कर दी गई है। दसवीं-बारहवीं परीक्षा के लिए आवेदन 26 अक्टूबर से भरे जाएंगे। आवेदन सामान्य शुल्क के साथ 25 नवंबर तक भरे जा सकेंगे। परीक्षा के आनलाइन आवेदन भरने की तिथि के गुरुवार को मंडल सचिव ने आदेश जारी कर दिए है। मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध स्कूलों में नियमित विद्यार्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया 30 सितंबर तक निर्धारित की गई थी। अब स्कूल में प्रवेशित नियमित प्रत्येक छात्र की नामांकन की जानकारी मंडल की वेबसाइट पर 31 अक्टूबर तक आनलाइन दर्ज कराना है। मंडल की परीक्षा के लिए केवल वही छात्र आवेदन कर सकेगा, जिसका विद्यालय द्वारा आनलाइन नामांकन कराया जा रहा है। 31 अक्टूबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मंडल ने नियमित व स्वाध्यायी छात्रों के लिए परीक्षा आवेदन भरने की तिथि भी घोषित कर दी है। परीक्षा के लिए वहीं छात्रा आवेदन कर सकेंगे, जिनका 31 अक्टूबर तक नामांकन हुआ है। दसवीं-बारहवीं परीक्षा के लिए आवेदन 26 अक्टूबर से आनलाइन भरना शुरू होंगे। 25 नवंबर तक सामान्य शुल्क के साथ फार्म भरे जाएंगे। 26 नवंबर से 10 दिसंबर तक विलंब शुल्क दो हजार रुपए रहेगा। 11 दिसंबर से 31 दिसंबर तक विलंब शुल्क पांच हजार रुपए रहेगा। एक जनवरी से 31 जनवरी तक विलंब शुल्क दस हजार रुपए रहेगा।

10वीं, 12वीं की परीक्षा के लिए आवेदन तिथि घोषित

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। प्रदेश के स्कूलों में अभी नियमित कक्षाएं लग नहीं रहीं। पाठ्यक्रम कटौती कर तय नहीं किया गया, लेकिन 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के आवेदन की तिथि घोषित कर दी गई है। 10वीं व12वीं परीक्षा के लिए आवेदन 26 अक्टूबर से भरे जाएंगे।

आवेदन सामान्य शुल्क के साथ 25 नवंबर तक भरे जा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि के संबंध में गुरुवार को आदेश जारी कर दिए हैं। मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध स्कूलों में नियमित विद्यार्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया 30 सितंबर तक निर्धारित की गई थी। अब स्कूल में प्रवेशित नियमित प्रत्येक छात्र की नामांकन की जानकारी मंडल की वेबसाइट पर 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन दर्ज कराना है। मंडल की परीक्षा के लिए केवल वही छात्र आवेदन कर सकेंगे, जिनका विद्यालय द्वारा ऑनलाइन नामांकन कराया जा रहा है। 31 अक्टूबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मंडल ने नियमित व स्वाध्यायी छात्रों के लिए परीक्षा आवेदन भरने की तिथि भी घोषित कर दी है। परीक्षा के लिए वही विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे, जिनका 31 अक्टूबर तक नामांकन हुआ है। 10वीं-12वीं परीक्षा के लिए आवेदन 26 अक्टूबर से आनलाइन भरना शुरू होंगे। 25 नवंबर तक सामान्य शुल्क के साथ फार्म भरे जाएंगे। 26 नवंबर से 10 दिसंबर तक विलंब शुल्क 2 हजार रुपये रहेगा। 11 से 31 दिसंबर तक विलंब शुल्क 5 हजार रुपये रहेगा। 1 जनवरी से 31 जनवरी 2021 तक विलंब शुल्क 10 हजार रुपये रहेगा।

9वीं व11वीं में विशिष्ट-सामान्य भाषा का भेद खत्म

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। स्कूल शिक्षा विभाग ने मप्र बोर्ड की इस सत्र से 9वीं से 12वीं तक के कई विषयों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की किताबें लागू कर दी हैं। 2020-21 व 2021-22 तक सभी किताबें एनसीईआरटी की लागू कर दी जाएगी।

इस सत्र में 9वीं व 11वीं में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत व उर्दू भाषा की किताबें एनसीईआरटी की ली गई हैं। इस संबंध में माशिमं ने गुरुवार को आदेश जारी किया है। अब इन कक्षाओं से विशिष्ट हिंदी एवं विशिष्ट अंग्रेजी की किताबें चलन से बाहर हो गई हैं, यानी सिर्फ एक हिंदी व अंग्रेजी होंगी। वहीं 10वीं और 12वीं में भाषा को अगले सत्र से बदले जाने का प्रस्ताव है। इस सत्र में केवल 10वीं और 12 वीं विशिष्ट अंग्रेजी एवं हिंदी रह गई है। बोर्ड ने जारी आदेश में 9वीं से 12वीं तक में एनसीईआरटी की किताबों के उपयोग का उल्लेख करते हुए 31 पाठ्यपुस्तकों की सूची जारी की है।

पहले से ही गणित व विज्ञान एनसीईआरटी की लागू

9वीं से 12 वीं तक गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान पिछले सत्र से ही एनसीईआरटी से पढ़ाया जा रहा था। इसके बाद इस सत्र में अन्य विषयों को बदला गया है जिससे सभी विषयों में एनसीईआरटी की पढ़ाई हो गई है।

10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन 26 अक्टूबर से

भोपाल (नईदुनिया प्रतिनिधि)। प्रदेश के स्कूलों में अभी नियमित कक्षाएं लग नहीं रहीं हैं। पाठ्यक्रम में कटौती कर तय नहीं किया गया, लेकिन 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के आवेदन भरने की तिथि घोषित कर दी गई है। 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन 26 अक्टूबर से भरे जाएंगे।

आवेदन सामान्य शुल्क के साथ 25 नवंबर तक भरे जा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि के संबंध में गुरुवार को आदेश जारी कर दिए हैं। मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध स्कूलों में नियमित विद्यार्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया 30 सितंबर तक निर्धारित की गई थी। अब स्कूल में प्रवेशित नियमित प्रत्येक छात्र की नामांकन की जानकारी मंडल की वेबसाइट पर 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन दर्ज कराना है। मंडल की परीक्षा के लिए केवल वही छात्र आवेदन कर सकेगा, जिसका विद्यालय द्वारा ऑनलाइन नामांकन कराया जा रहा है। 31 अक्टूबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मंडल ने नियमित व स्वाध्यायी छात्रों के लिए परीक्षा आवेदन भरने की तिथि भी घोषित कर दी है। परीक्षा के लिए वही विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे, जिनका 31 अक्टूबर तक नामांकन हुआ है। 10वीं-12वीं परीक्षा के लिए आवेदन 26 अक्टूबर से ऑनलाइन भरना शुरू होंगे। 25 नवंबर तक सामान्य शुल्क के साथ फॉर्म भरे जाएंगे।

9वीं व 11वीं में विशिष्ट और सामान्य भाषा खत्म कर एक समान होगी

भोपाल (नईदुनिया प्रतिनिधि)। स्कूल शिक्षा विभाग ने मप्र बोर्ड की इस सत्र से 9वीं से 12वीं तक के कई विषयों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की किताबें लागू की है। सत्र 2020-21 व 2021-22 तक में 9वीं से 12वीं तक की सभी किताबें एनसीईआरटी की लागू कर दी जाएगी। इस सत्र में 9वीं व 11वीं में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत व उर्दू भाषा की किताबें एनसीईआरटी की ली गई है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने गुरुवार को आदेश जारी किया है कि इस सत्र से 9वीं एवं 11वीं के सभी विषय एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाए जाएंगे। अब इन कक्षाओं से विशिष्ट हिंदी एवं विशिष्ट अंग्रेजी की किताबें चलन से बाहर हो गई हैं, यानि सिर्फ एक हिंदी व अंग्रेजी होंगी। वहीं 10वीं और 12वीं में भाषा को अगले सत्र से बदले जाने का प्रस्ताव है। इस सत्र में केवल 10वीं और 12वीं विशिष्ट अंग्रेजी एवं हिंदी रह गई है। बोर्ड ने जारी आदेश में 9वीं से 12वीं तक में की किताबों के उपयोग का उल्लेख करते हुए 31 पाठ्यपुस्तकों की सूची जारी की है।

पहले से ही गणित व विज्ञान एनसीईआरटी की लागू

9वीं से 12वीं तक गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान पिछले सत्र से ही एनसीईआरटी से पढ़ाया जा रहा था। इसके बाद इस सत्र में अन्य विषयों को बदला गया है जिससे सभी विषयों में एनसीईआरटी की पढ़ाई हो गई है।

कक्षा 9, 11 व 12वीं में हिंदी व अंग्रेजी भाषा के दो ही विषय होंगे

भोपाल| माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित 9वीं, 11वीं और 12वीं में हिंदी व अंग्रेजी भाषा के विशिष्ट व सामान्य विषय नहीं होंगे। अब से सिर्फ दो ही विषय हिंदी एवं अंग्रेजी होंगे। पुस्तकें भी अब इनकी अलग-अलग नहीं होंगी। ये पुस्तकें एनसीईआरटी की ही होंगी। मंडल ने अन्य विषयों के साथ इन विषयों की पुस्तकों की सूची जारी कर दी है। अभी तक राज्य शिक्षा केंद्र के अधीन मप्र पाठ्य पुस्तक स्थाई समिति द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार ही इन विषयों की पुस्तकों से पढ़ाई कराई जा रही थी। करीब तीन साल पहले गणित, विज्ञान विषयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू की गईं थी। अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा इसमें शामिल नहीं थी। अभी तक अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी विशिष्ट अंग्रेजी और सामान्य हिंदी विषय लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी विशिष्ट हिंदी और सामान्य अंग्रेजी विषय लेकर पढ़ाई कर रहे हैं।

सीबीएसई ने ऑनलाइन क्लास का बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

24 घंटे तक 8वीं के 13,000 स्टूडेंट्स ऑनलाइन एआई क्लास में हुए शामिल

नई दिल्ली, जेएनएन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने 14 अक्टूबर को सबसे ज्यादा यूजर्स को 24 घंटे में ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की क्लास देने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का खिताब हासिल किया है। 8वीं के 13,000 स्टूडेंट्स के लिए 13 से 14 अक्टूबर के बीच आयोजित ऑनलाइन क्लास के चलते यह रिकॉर्ड सेट किया गया है। इस बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट के जरिये सीबीएसई को बधाई भी दी है। यह ऑनलाइन क्लास इंटेल और सीबीएसई द्वारा आयोजित की गई थी। इंटेल में ग्लोबल पार्टनरशिप और इनिशिएटिव की निदेशक श्वेता खुराना ने एक बयान में बताया कि देश के स्टूडेंट्स की ओर से ऑनलाइन एआई प्रशिक्षण के लिए उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया के कारण ही वे इस रिकॉर्ड को बना पाए हैं। देश के एजुकेशन सिस्टम में एआई की भूमिका को बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने इंटेल और सीबीएसई दोनों को एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया था। इनमें से प्रत्येक पाठ उन शिक्षकों द्वारा लिखा गया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित मार्गदर्शन के मुताबिक स्टूडेंट्स को एक अनुभवात्मक और सुखद तरीके से समग्र ज्ञान प्राप्त करने में विषय विशेषज्ञ हैं।

11 दिन में 12 हजार किमी. उड़कर चिड़िया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

बार-टेल्ड गॉडविट नाम की चिड़िया ने बिना रुके 12 हजार किलोमीटर की दूरी 11 दिन में पूरी की। चिड़िया ने यह दूरी अलास्का से न्यूजीलैंड के बीच तय करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस दौरान उसने न तो कुछ खाया और न ही पानी पिया। चिड़िया को ट्रैक करने के लिए वैज्ञानिकों ने उसके शरीर के पिछले हिस्से पर सैटेलाइट टैग लगाया। माइग्रेशन पर रिसर्च करने वाली वैज्ञानिक डॉ. जेसी कॉन्कलिन कहती हैं, गॉडविट का शरीर लड़ाकू विमान जैसा है और लम्बे-नुकीले पंख उसे हवा में तेज उड़ने की क्षमता देते हैं। डॉ. जेसी कहती हैं, गॉडविट चिड़िया ने 16 सितम्बर को उड़ान भरी। उड़ने से पहले उसने दो महीने तक कीड़े और रोटी खाई। सफर के दौरान वह 88 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ी और 27 सितम्बर को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंची। वैज्ञानिकों के मुताबिक, जब यह चिड़िया उड़ती है तो अपने शारीरिक अंगों को सिकोड़ लेती है, इस कारण इसका शरीर काफी छोटा हो जाता है।

राजधानी में स्कूलों को खोलने और ना खोलने को लेकर गतिरोध बरकरार

सीबीएसई स्कूल: बच्चे कक्षा में आएं

अभिभावक बोले: हम रिस्क नहीं लेंगे

पालक बोले जब तक वैक्सीन नहीं आती, तब तक बच्चों को स्कूल भेजना उचित नहीं

यदि विद्यालय बच्चों की पूरी गारंटी ले तभी हम इन्हें स्कूल भेज सकते हैं

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

आधा सत्र गुजरने की अंतिम बेला में सीबीएसई स्कूलों ने कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के बच्चों से नियमित रूप से कक्षाओं में बैठने का आह्वान किया है। स्कूलों की इस मांग पर असहमति जताते हुए अभिभावकों ने कहा कि हम इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेंगे। सीबीएसई स्कूलों के सहोदय ग्रुप ने हाल ही में अभिभावकों से अपील की है कि वह अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें। यह अपील सिर्फ कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के बच्चों के लिए की गई है।

इधर पालकों ने दो टूक शब्दों में कहा है कि हम ऐसी भीषण महामारी में कोई रिस्क नहीं लेंगे। हां यदि स्कूल पूरी गारंटी ले तो हम अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। अभिभावकों ने तर्क भी दिया है कि खासकर राजधानी भोपाल और इंदौर में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस महामारी के बीच बच्चों को स्कूल भेजने में डर लग रहा है। नतीजतन हम अपनी सहमति पर बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते हैं। क्योंकि अगर घातक बीमारी का संक्रमण बच्चों पर हुआ तो फिर बड़ी चिंताओं को सहना पड़ेगा।

मार्गदर्शन दिलाने में भी पालक दहशत में आए

बताना होगा कि पिछले माह राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसके तहत कक्षा नवीं से बारहवीं तक के बच्चे कक्षाओं में अभिभावकों की सहमति पर शिक्षक से मार्गदर्शन लेने पहुंच सकते हैं। कोविड- 19 के नियमों का पालन करते हुए पालक की लिखित सहमति पर बच्चे विषय की बारीकियां सीखने स्कूल जा सकते हैं। सरकार का आदेश जारी होने के बावजूद राजधानी में अधिकांश पालक अभी भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। अभिभावक करोड़ी सिंह मीनाक्षी सहित अन्य का कहना है कि हम कोई लिखित सहमति देकर बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते हैं। क्योंकि बीमारी तेजी से फैल रही है।

अपील को अभिभावकों ने किया अस्वीकार

सहोदय ग्रुप में वाइस प्रेसिडेंट पीके पाठक का कहना है कि हमने नौवीं से बारहवीं तक के बच्चों को स्कूल आने का अनुरोध किया था। इस अपील के पीछे लॉजिक यही था कि बच्चे विधिवत पढ़ाई करें, लेकिन अभिभावकों ने इस अनुग्रह को स्वीकार नहीं किया। पाठक का कहना है कि अभिभावकों ने तेजी से फैल रहे कोरोना का हवाला देते हुए यही शर्त रखी है कि अगर स्कूल प्रबंधन बच्चे की स्वास्थ्य सुरक्षा की पूरी गारंटी ले तभी हम उसे स्कूल भेज सकते। श्री पाठक का कहना है कि यह गारंटी लेना संभव नहीं है।

सिर्फ मार्गदर्शन ही उचित: बघेल

इधर मप्र स्कूल शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल संगठन के संरक्षक आरके सिंह बघेल का कहना है कि राज्य सरकार का आदेश सिर्फ बच्चों को अभिभावकों की सहमति पर स्कूल बुलाकर मार्गदर्शन देने का है। मौजूदा समय में मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल इसी सिस्टम पर काम कर रहे हैं। बघेल का कहना है कि सीबीएसई स्कूलों में भी फिलहाल यही प्रक्रिया होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास दो चुनौतियां हैं। पहले तो बच्चों का समय से कोर्स पूरा कराना है। दूसरी हमें बच्चों के अलावा शिक्षकों के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है।

जब तक वैक्सीन नहीं, नहीं भेजेंगे स्कूल

अभिभावक प्रीति चौहान का कहना है कि जब तक वैक्सीन मार्केट में नहीं आ जाती है। तब तक बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जाना चाहिए। वर्तमान में जो अभिभावक सहमति पर बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। उन्हें तब तक चिंता रहती है जब तक बच्चे सकुशल घर नहीं लौट आता है। डर यह भी बना रहता है कि कहीं बच्चा कोरोना की चपेट में ना आ जाए। इस कारण वैक्सीन का इंतजार स्कूलों को करना होगा। उसके बाद ही नियमित कक्षाएं लगाई जाए।

पढ़ाई चले, तरीका निकालना होगा

अभिभावक शिवम चौरसिया का कहना है कि कोरोना संकट में बच्चों की पढ़ाई नियमित चले और बच्चे सुरक्षित रहे। ऐसा तरीका निकालना होगा। स्कूलों में अगर बच्चों को बुलाया जाता है तो फिर भीड़ ना बढ़े ऐसी व्यवस्था जरूरी है। क्योंकि एक साथ चार कक्षाओं के बच्चे स्कूलों में आएंगे तो तो भीड़ इकट्ठा होगी। इस कारण हर दिन एक कक्षा का समय निर्धारित होना चाहिए और स्कूल वालों को अपनी गारंटी पर बच्चों को स्कूल बुलाया जाना चाहिए।

बच्चा बीमार हुआ तो जवाबदार कौन...?

शिक्षक एवं तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ में शिक्षा समिति के जिला संयोजक जितेंद्र चौहान का कहना है कि अगर बच्चा स्कूल आता है और वह बीमार हो जाता है तो उसका जवाबदार कौन होगा। जब से लॉकडाउन खुला है तब से हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लोग स्वयं कोविड.19 के नियमों का पालन करने में गंभीर नहीं है। यही कारण है कि कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है।

अतिथि विद्वान की भर्ती में किसी को रोका नहीं जा सकता है, नए उम्मीदवार शामिल किए जाए

ग्वालियर (नवदुनिया प्रतिनिधि)। हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की एकल पीठ ने अतिथि विद्वान की भर्ती में सभी को मौका दिए जाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश दिया है। भर्ती में किसी को शामिल होने से रोका नहीं जा सकता है।

उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज में अतिथि विद्वानों की भर्ती के लिए सूचना जारी की थी। इसमें उन्हीं शिक्षकों को शामिल किया जा रहा था, जिन्होंने सत्र 2019-20 में कॉलेज में अतिथि विद्वान के रूप में पढ़ाया हो। नए उम्मीदवार को इसमें शामिल होने पर रोक लगा दी थी। मनोज सिंह ने हाई कोर्ट में उच्च शिक्षा विभाग के आदेश को चुनौती दी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आकाश शर्मा व हिमांशु शर्मा ने तर्क दिया कि अतिथि शिक्षक की भर्ती में नए उम्मीदवार को रोका नहीं जा सकता है। यह अधिकारों का उल्लंघन है। सभी को मौका दिया जाना चाहिए। इंदौर खंडपीठ ने भी आदेश दिया है कि सभी को शामिल किया जाए। ग्वालियर खंडपीठ ने भी अतंरिम आदेश पारित कर सभी को शामिल किए जाने का आदेश दिया है।

सिलावट के खिलाफ चुनाव याचिका में दोबारा होगी सुनवाई

इंदौर (नप्र)। तुलसीराम सिलावट के खिलाफ दायर जिस चुनाव याचिका को याचिकाकर्ता ने खुद ही वापस ले लिया था उसकी सुनवाई दोबारा शुरू होगी। गुरुवार को इस संबंध में एक पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत हुई है। कोर्ट ने इसकी सुनवाई करते हुए सप्ताहभर पहले दिए याचिका वापस लेने की अनुमति के आदेश पर रोक लगाते हुए सिलावट व अन्य को नोटिस जारी कर दिए हैं। याचिका सांवेर विधानसभा क्षेत्र के एक मतदाता पवन सिंह ने पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता रवींद्र सिंह छावड़ा के माध्यम से दायर की है। छावड़ा ने बताया कि चुनाव याचिका वापस लेने का आवेदन प्रस्तुत होने पर सभी पक्षकारों को सूचना पत्र जारी करना और उसका प्रकाशन राजपत्र में किया जाना आवश्यक होता है। राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात ऐसे व्यक्ति जो चुनाव याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार रखते थे, कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर याचिकाकर्ता के स्थान पर स्वयं को प्रतिस्थापित करने और चुनाव याचिका का संचालन स्वयं करने के लिए आवेदन दे सकते हैं।

ट्रायवल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन जिला शाखा डिण्डौरी ने

बी.ई.ओ. के विरुद्ध जांच कराने की मांग

हरिभूमि न्यूज डिण्डौरी। ट्रायवल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन जिला शाखा ने केन्द्रीय इस्पात मंत्री को विकासखण्ड षिक्षा अधिकारी संजय सिंह तोंमर को बीईओ पद से पृथक किये जाने एवं विभागीय जांच किये जाने को लेकर केन्द्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को मांग पत्र सौपे है जिसमे उल्लेख किया गया है कि संजय सिंह तोमर (प्राचार्य शास. उच्च. माध. विद्यालय बिछिया) वर्तमान मे विकासखण्ड षिक्षा अधिकारी शहपुरा के अतिरिक्त प्रभार मे कार्यरत है जबकि जानकारी अनुसार शासन के निर्देष मे विकासखण्ड षिक्षा अधिकारी के पद का दायित्व संबंधित विकासखण्ड के वरिष्ठ प्राचार्य को दिये जाने का प्रावधान है, जिसके अनदेखी कर कनिष्ठ संजय सिंह तोमर को बीईओ का प्रभार दिया गया है। षिकायत पत्र मे यह भी उल्लेख किया गया है कि खेलों इंडिया फिट मूवमेन्ट के तहत शाला प्रबंधन समिति के खाते मे 5000 एवं 10000 की राषि से क्रय किये जाने वाली सामग्री बीईओ शहपुरा के द्वारा अपने पद का दवाव बनाते हुये घटिया खेल सामग्री की खरीददारी कराई गई। इसी तरह शीलिमा पटेल षिक्षिका प्राथमिक षिक्षा केन्द्र धिरवन कला वि.ख. शहपुरा को बीईओ शहपुरा के द्वारा 25.09.2020 को बीइओ शहपुरा कार्यालय मे सायं 4.30 बजे बुला कर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया जिसकी षिकायत शीलिमा पटैल के द्वारा शहपुरा थाने मे दर्ज कराई गई थी पर इस मामले पर भी बीईओ शहपुरा पर कोई कार्यवाही न किये जाने से उनके हौसले बुलंद हो गये है।

डीईओ के 100% उपस्थिति के आदेश का विरोध

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
मो.नं. 9893231237

केंद्र की गाइड लाइन पर स्कूल शिक्षा विभाग ने 15 अक्टूबर से 50 प्रतिशत शिक्षकों की उपस्थिति के साथ स्कूल खोलने के आदेश दिए हैं। इधर, दूसरी ओर व्यवस्थाओं को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 100 प्रतिशत उपस्थिति होने का आदेश जारी किया है। इस आदेश का कई शिक्षक संगठन विरोध कर रहे हैं। शिक्षक संगठनों ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में सभी कर्मचारियों को कार्यालय बुलाना सही नहीं होगा। संगठनों ने मांग की है कि पूर्व की तरह उन्हें 50-50 के नियम से बुलाया जाए। हालांकि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि काम की अधिकता को देखते हुए फिलहाल यह आदेश सिर्फ डीईओ कार्यालय के लिए जारी किया गया है। डीईओ ने 50-50 प्रतिशत उपस्थिति के 29 सितंबर 2020 के आदेश को निरस्त करते हुए कहा है कि कार्य की अधिकता को देखते हुए सभी कर्मचारियों की 14 अक्टूबर से कार्यालय में उपस्थिति नियमित होगी।

व्यवस्था को देखते हुए दिए आदेश

जिले के अन्य कार्यालयों में भी 100 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य की गई है और कर्मचारी काम कर रहे हैं। हमने व्यवस्थाओं को देखते हुए ही यह आदेश जारी किए हैं।

नितिन सक्सेना, जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल

डीईओ ने दिए 100% हाजिरी के आदेश, शिक्षक संगठन ने किया विरोध

सभी कर्मचारियों को एक साथ कार्यालय बुलाना खतरनाक

हरिभूमि न्यूज ⏭ भोपाल

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 100 प्रतिशत उपस्थिति होने का आदेश जारी होने के बाद कई शिक्षक संगठन इसके विरोध में आ गए हैं। शिक्षक संगठनों ने आदेश का विरोध करते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में सभी कर्मचारियों को कार्यालय में एक साथ बुलाना सही नहीं होगा। संगठनों ने मांग की है कि पूर्व की तरह की कर्मचारियों को कार्यालय में 50-50 के नियम से बुलाया जाए। ताकि कोरोना संक्रमण से बचाव हो सके। अधिकारियों का कहना है कि काम की अधिकता के चलते यह आदेश सिर्फ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिए जारी है। बता दें कि डीईओ ने बीते मंगलावार को 50-50 प्रतिशत उपस्थिति के आदेश को निरस्त करते हुए कहा है कि सभी कर्मचारी की 14 अक्टूबर से कार्यालय में उपस्थिति नियमित होगी।

बचाव के लिए 50-50 कर्मचारी बुलाएं

कार्यालय हो अथवा शैक्षणिक संस्थाए वर्तमान समय में 100 कर्मचारियों की उपस्थिति कोरोना महामारी को बढ़ावा दे सकती है। अत: डीईओ भोपाल का निर्णय आज की स्थिति में उचित नहीं है। कोरोना गाडलाइन के अनुसार 50-50 कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित होना चाहिए।

उपेट कौशल, प्रदेश संयोजक शासकीय अध्यापक संगठन, मप्र

आदेश निरस्त किया जाना चाहिए

कोरोना संक्रमण को देखते हुए कार्यालयों में कर्मचारियों की 50-50 उपस्थिति होनी चाहिए। 100 प्रतिशत उपस्थिति के इस आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए।

अरविंद भूषण श्रीवास्तव, प्रदेश संयोजक

व्यवस्थाओं को देखते हुए दिए आदेश

जिले के अन्य कार्यालयों में भी 100 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य की गई है और कर्मचारी काम कर रहे हैं। हमने व्यवस्थाओं को देखते हुए ही यह आदेश जारी किए हैं।

नितिन सक्सेना, जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल

बीए में सर्वाधिक दिखा विद्यार्थियों का रूझान, बीकॉम से ढाई गुना अधिक हुए बीए में प्रवेश

भोपाल। प्रदेश के 1405 निजी और सरकारी कॉलेजों में प्रवेश प्रवेश थम गया है। अभी तक स्नातक और स्नातकोत्तर में करीब 4 लाख प्रवेश हुए हैं। यूजी में करीब 2 लाख 97 हजार, वहीं पीजी में 1 लाख विद्यार्थियों ने प्रवेश हुए हैं। छात्रों का रुझान बीए, बीएससी में प्रवेश के लिए बीकॉम की अपेक्षा अधिक दिखा है। बीए में सर्वाधिक 1 लाख 38000 हजार छात्र-छात्राओं ने प्रवेश लिया है। शिक्षा विदों के अनुसार बीए में सबसे ज्यादा प्रवेश ग्रामीण क्षेत्रों की सीटों पर हुए हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में भी विद्यार्थी बीए में ग्रेजुएशन करने के साथ ही यूपीएससी, एमपीएससी सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। बीए में बीकॉम की अपेक्षा ढाई गुना अधिक एडमिशन हुए हैं।

छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित

भोपाल। सामाजिक न्याय एवं नि: शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों में दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। विभिन्न योजनाओं के तहत विद्यालय या स्वयंसेवी संस्थाओं में कक्षा 1 से 12 तक शिक्षणरत दिव्यांग छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति, महाविद्यालय या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षणरत् दिव्यांग छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं वाचक भत्ता दिया जाता है। साथ ही 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर कक्षा 8वीं से 9वीं, 10 से 11वीं एवं 12वीं से स्नातक में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण ने बताया कि दिव्यांग छात्र-छात्राएं निर्धारित छात्रवृत्ति के फार्म में विद्यालय, महाविद्यालय अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था की अनुशंसा के साथ बैंक का खाता क्रमांक, आईएफएससी कोड क्रमांक, शाखा का नाम का स्पष्ट उल्लेख करते हुए समग्र आईडी, आधार कार्ड एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र, विद्यालय से उत्तीर्ण की गई अंक सूची के साथ नवम्बर माह के अंत तक आवेदन कर सकते हैं।

दिव्यांग बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने की शुरुआत की

भोपाल। दिव्यांगज बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए महामारी के इस दौर में विशेष शिक्षक सहारा बन रहे हैं। कोविड19 के कारण जहां पूरा देश महामारी से

लड़ रहा है। वही हमारे कुछ समाजसेवी बच्चों को इस परिस्थिति में भी शिक्षा से जोड़ने की पहल कर रहे है। सीडब्ल्यूएसएन बिशन खेड़ी दिव्यांग छात्रावास में पढ़ने वाले उन सभी दिव्यांग बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने की शुरुआत की गई है जो कोरोना काल में अपने घरों पर रह रहे हैं। देवव्रत ग्राम विकास शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष शिवांसु शुक्ला का कहना है कि समिति के प्रयासों से दिव्यांग बच्चों को ऑनलाइन व वीडियो कॉलिंग करके बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। प्रतिदिन 5 बच्चों के घर मे जाकर भी उन्हें शिक्षित किया जा रहा है। जिससे कि उनकी शिक्षा में रुकावट न आये।

विद्यालय संचालक को महिला लेखाधिकारी ने लगाई 44 लाख रुपए की चपत

रकम लेकर महिला फरार, जांच के बाद मामला दर्ज

ग्वलियर, न.सं.

विद्यालय में लेखाधिकारी ने छात्रों को फर्जी रसीद देकर लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा कर गबन कर दिया। विद्यालय संचालक ने जब रकम के बारे में महिला लेखाधिकारी से रकम के बारे में पूछा तब फर्जीवाड़े का पता चला। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश प्रारंभ कर दी है।

थाटीपुर थाने के पास स्थित अमर भारती विद्यालय में चांदनी राजा बुंदेला पुत्री विजयसिंह लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत थीं। पूरे विद्यालय का लेखा-जोखा चांदनी के पास ही रहता था। वर्ष 2017 में लेखाधिकारी चांदनी ने शुल्क के फर्जी रसीद कट्टे से छात्रों की शुल्क लेकर विद्यालय को चपत लगाना शुरू कर दिया। इस मामले की उन्होंने विद्यालय संचालक देवेन्द्र सिंह चौहान को भनक तक नहीं लगने दी।

बताया गया है कि महिला लेखाधिकारी ने छात्रों की शुल्क लेकर कुछ बैंक में जमा की तो कुछ को अपने पास रख लिया। इस तरह तीन साल तक चांदनी ने विद्यालय का 44 लाख रुपए बैंक में जमा ही नहीं किया। संचालक देवेन्द्र चौहान को जब बैंक खाते में रकम के कम जमा होने पर शंका हुई तो उन्हें मामला

संदिग्ध लगा और चांदनी बुंदेला से पूछताछ की। लेकिन उन्होंने शुल्क का ब्यौरा देने के लिए कहा। वर्ष 2017 से लेकर आज तक 44 लाखों रुपए के फर्जीवाड़े की शिकायत संचालक ने पुलिस से की। जांच के बाद पुलिस ने चांदनी के खिलाफ धारा 406 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है।

प्लाट बेचने का झांसा देकर ठगी

बहोड़ापुर थाना क्षेत्र स्थित आनंद नगर निवासी साबी बग्गा पुत्र रतनलाल को शरद मिश्रा और जयप्रकाश ने प्लाट बेचने का झांसा देकर ठगी का शिकार बना लिया। जब फर्जीबाड़े का फरियादी को पता चला तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की। पुलिस का कहना है कि ठगी पैसों की जरूरत कहकर की गई है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश प्रारंभ कर दी गई है।

दिव्यांग छात्रवृत्ति के लिए करें आवेदन

भोपाल। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांग छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। विभिन्न योजनाओं के तहत विद्यालय या स्वयंसेवी संस्थाओं में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाले दिव्यांग छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति, महाविद्यालय या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षणरत दिव्यांग छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। साथ ही 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करनें पर 8वीं से स्नातक में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

आठवीं तक के शिक्षकों का ऑनलाइन 'निष्ठा' प्रशिक्षण आज से होगा शुरू

भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग कक्षा एक से 8वीं तक के समस्त शिक्षकों के लिए एनसीईआरटी के

कार्यक्रम

तय मॉड्यूल पर निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार से शुरू कर रहा है। पूर्व में 'निष्ठा' से प्रशिक्षण प्राप्त एसआरजी एवं केआरपी हर विकासखंड में सहयोग देंगे। शैक्षिक संवाद कार्यक्रम में भी एसआरजी अकादमिक सहयोग प्रदान करेंगे। प्रत्येक शिक्षक को 18 मॉड्यूल का प्रशिक्षण पूर्ण करने पर ही एनसीईआरटी से कोर्स पूर्णता का प्रमाण-पत्र एवं एक हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर राज्य के कंट्रोल रूम के फोन नं.-0755-2552368 पर संपर्क कर सकते हैं।

दो साल से जमीन अलाटमेंट के लिए धूल खा रहा प्रस्ताव

स्मार्ट सिटी में प्रदेश का पहला कन्या संस्कृत विद्यालय तोड़ा

रशीदिया स्कूल की आधी बिल्डिंग में चल रहा विद्यालय

शहर प्रतिनिधि, भोपाल

संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश का पहला संस्कृत विद्यालय स्मार्ट सिटी में फटाफट खाली कराकर तोड़ दिया गया। तोड़ते समय आश्वासन दिया कि जल्द ही जमीन का अलाटमेंट कर नया विद्यालय बनाकर दिया जाएगा। दो साल बीतने के बाद भी स्कूल बनना तो दूर जमीन अलाटमेंट का प्रस्ताव भी कलेक्ट्रेट में धूल खा रहा है। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान द्वारा संचालित प्रदेश का पहला कन्या संस्कृत विद्यालय तीन साल पहले टीटी नगर क्षेत्र में खोला गया था। इस विद्यालय में अनूपपुर, टीकमगढ़, शहडोल, बैतूल, शिवपुरी, बालाघाट समेत अन्य आदिवासी बहुल जिलों की 160 छात्राएं अध्ययनरत हैं। दो साल पहले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्कूल को खाली करना था। इसके पहले स्मार्ट सिटी ने आश्वासन दिया था कि स्कूल खाली करते ही दूसरी जगह जमीन का अलाटमेंट कर दिया जाएगा। साथ ही छात्राओं के पढ़ने के लिए अन्य जगह व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद स्कूल को जहांगीराबाद इलाके में पुराना रशीदिया स्कूल में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया। जहां पर छात्रावास की समस्या है। स्कूल के लिए जिला प्रशासन की तरफ से जगह चिन्हित करने के लिए कहा गया। संस्कृत संस्थान ने अल्कापुरी कालोनी में 3 एकड़ जमीन चिन्हित कर दे दी। लेकिन बीते दो साल से स्कूल बनना तो दूर उसकी फाइल जिला प्रशासन के पास दबी हुई है।

पचास साल पुराने स्कूलों को तोड़ा, लेकिन नहीं दी जमीन : स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कई सरकारी और 50 साल पुराने स्कूलों को भी हटाया गया है। इनमें टीटीनगर क्षेत्र के 3 निजी और 8 सरकारी स्कूल शामिल है। सभी स्कूलों को दूसरे जगह अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया है। लेकिन इनके लिए अभी तक जमीन अलाट नहीं की गई है। जहांगीराबाद इलाके के रशीदिया स्कूल में कन्या संस्कृत विद्यालय को शिफ्ट किया गया है। यहां छात्राओं का हाल में छात्रावास है। पढ़ने के लिए उपयुक्त व्यवस्था भी नहीं है।

स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्कूल को शिफ्ट किया गया था। जमीन अलाटमेंट के लिए प्रस्ताव बनाकर दे दिया है। प्रशासन से जमीन अलाट हो जाएगी, तो आगे की कार्यवाही प्रारंभ करेंगे।

प्रभात आर तिवारी, संचालक
महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान

इंजीनियरिंग कॉलेजों में फीस जमा करने का आज आखिरी दिन

नसं, भोपाल। इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिएं करीब 21 हजार विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। कॉलेजों की खाली 55 हजार सीटों के लिए एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण में जेईई-मेन के पात्र विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग शुरू हुई है। पंजीयन करा चुके विद्यार्थियों को 16 अक्टूबर तक संबंधित कॉलेजों में फीस जमा करना होगी। छात्रों के दस्तावेजों का सत्यापन इस बार कॉलेजों में ही होगा। इसके बाद छात्रों को अपग्रेडेशन का विकल्प भी दिया जाएगा। अपग्रेडेशन वाले छात्रों को 19 से 23 अक्टूबर तक एडमिशन लेना होगा। बारहवीं के अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को 13 से 24 अक्टूबर तक पंजीयन का मौका मिलेगा। इसके बाद 21 से 27 अक्टूबर तक छात्र च्वाइस फिलिंग करा सकते हैं।

शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ दिये जाने की मांग

मऊगंज ब्यूरो। वर्ष 1997-98 से शिक्षा गारंटी योजना से नौकरी की शुरूआत करने वाले गुरूजियों को भी वरिष्ठता एवं क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ मिलना चाहिये। सर्व शिक्षक संघ के प्रान्ताध्यक्ष सतानन्द मिश्र ने कहा है कि, वर्ष 2008 से जिनका प्राथमिक शिक्षक के पदों पर संविलियन हुआ है, वे सभी प्रथम क्रमोन्नति के पात्र हैं। प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी समय सीमा में इनको क्रमोन्नति का लाभ प्रदान करें। क्रमोन्नति प्रस्ताव सभी संकुल प्राचार्य तत्काल भेजना सुनिश्चित करें। अन्य शिक्षक संवर्ग की जो क्रमोन्नति हुई है,जिनमें कई लोग छूट गये हैं,उनका भी निराकरण किया जाय। सहायक शिक्षक विज्ञान की क्रमोन्नति सूची अकारण प्रतीक्षारत है,जिसका प्रकाशन तत्काल कराये जाने की मांग की गई है।

अगले सत्र से नवमीं से बारहवीं तक पूरा सिलेबस होगा एनसीईआरटी

भोपाल, शप्र। मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध सभी स्कूलों में अगले सत्र से एनसीईआरटी की लगभग सभी किताबें लागू कर दी जाएगी। वर्तमान सत्र में नवमीं, 11वीं के लगभग सभी विषय एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाए जाएंगे। इस तरह इन कक्षाओं से विशिष्ट हिंदी एवं विशिष्ट अंग्रेजी की किताबें चलन से बाहर हो गई हैं। 10 वीं और 12 वीं में यह किताबें है, जिनके अगले सत्र से बाहर कर एनसीईआरटी की किताबों को लागू कर दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नवमीं से बारहवीं तक का पूरा सिलेबस एनसीईआरटी की किताबों का लागू किया जा रहा है। बीते तीन सालों से यह प्रक्रिया शुरू हुई है। हर साल धीरे-धीरे प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान सत्र 2020-21 के लिए माशिमं के जारी आदेश में एनसीईआरटी की किताबों के उपयोग का उल्लेख करते हुए सूची जारी की है। हालांकि यह इस सत्र के प्रारंभ से व्यवहारिक रूप से पालन हो रहा है लेकिन आदेश स्पष्टता के लिए जारी किए गए। नवमीं से 12 वीं तक गणित और विज्ञान पहले ही एनसीईआरटी से पढ़ाया जा रहा था। मंडल अधिकारियों का कहना है कि अगले साल लगभग सभी क्लास में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू कर दिया जाएगा।

सीएम हेल्पलाइन पर अब शिकायत करना हुआ आसान

काल करने की जरूरत नहीं व्हाट्सप पर हो सकेगी शिकायत

भोपाल, काप्र। प्रदेश के आम लोगों के लिए अच्छी खबर है। आम लोगों को अब सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करना और आसान हो गया है। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत सुविधा अब वॉट्सऐप पर भी हो गई है। अब कोई भी व्यक्ति कहीं से भी सीएम हेल्पलाइन पर कॉल किए बिना शिकायत कर सकता है।

वह शिकायत की वर्तमान स्थिति के बारे में भी तत्काल जान सकता है। इसके लिए उसे ना तो ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे और ना ही किसी अधिकारी या कर्मचारी के सामने गिड़गिड़ाना होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए वॉट्सऐप नंबर जारी कर दिया है। इसके माध्यम से मोबाइल फोन से किसी भी तरह की शिकायत तत्काल करना संभव हो गया है।

इस नंबर पर शिकायत की जा सकती है

मध्यप्रदेश सरकार ने लोगों की मदद के लिए एक वॉट्सऐप नंबर जारी किया है। कोई भी वॉट्सऐप नंबर +91-7552555582 पर अब कहीं से कोई भी शिकायत कर सकता है। उसे बस अपने मोबाइल फोन पर इस नंबर को सेव करना होगा। उसके बाद वॉट्सऐप ऑप्शन में जाकर वह अपनी बात रख सकते हैं। अपनी तरफ से सिर्फ हाए लिखना होता है। उसके बाद चार विकल्प सामने आते हैं। इसमें शिकायत की स्थिति, नवीन शिकायत दर्ज कराना, योजनाओं की जानकारी और अन्य जानकारी शामिल होती है। बस अपना प्रश्न या अपनी समस्या मैसेज के रूप में लिखनी होगी। आगे की प्रोसेस अपने आप होती जाती है। बस प्रोसेस के अनुसार जवाब देना होता है। किसी योजना की जानकारी के लिए इसमें एक लिंक आती है। इस पर सरकारी की योजनाओं के बारे में जानकारी भी मिल जाती है।

बिना कमिश्नर के चल रहा उच्च शिक्षा विभाग, प्रोफेसर संभाल रहे व्यवस्थाएं

नगर संवाददाता, भोपाल

प्रदेश के 1400 से ज्यादा सरकारी और निजी कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। इनमें खाली 9 लाख से ज्यादा सीटों को भरे जाने के लिए काउंसलिंग का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में भी उच्च शिक्षा विभाग बिना कमिश्नर के चल रहा है। उच्च शिक्षा विभाग के कमिश्नर मुकेश शुक्ला को 23 सितंबर को हटा दिया था। इसके बाद से सरकार यहां कमिश्नर की नियुक्ति नहीं कर पाई है। इससे यहां की व्यवस्थाएं अब उच्च शिक्षा विभाग में पदस्थ कॉलेजों के प्रोफेसर ही संभाल रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग के कमिश्नर का पद इतने लंबे समय तक कभी खाली नहीं रहा है। यह पहला मौका है, जब डेढ़ महीने बाद भी नए कमिश्नर की नियुक्ति सरकार नहीं कर पाई है, जबकि इस बार कोरोना काल की वजह से परीक्षा कराना, परीक्षा परिणाम जारी करना और नए शिक्षण सत्र की शुरुआत सहित कई महत्वपूर्ण काम चुनौती भरे हैं। एडमिशन प्रक्रिया पहले ही लेट हो चुकी है। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के बाद विश्वविद्यालयों ने परीक्षाएं तो करा दीं हैं, लेकिन अब परीक्षा परिणाम जारी नहीं कर पा रहे हैं। परीक्षा परिणाम जारी करने में विश्वविद्यालय लेट हो चुके हैं।

ये प्रोफेसर संभाल रहे व्यवस्थाएं

अभी उच्च शिक्षा विभाग में धीरेंद्र शुक्ला, पीएल सरोडिया, अनिल पाठक, पूर्णिमा लूधबाल, आलोक वर्मा, अजय खरे सहित अन्य प्रोफेसर विभिन्न शाखाओं के ओएसडी हैं। इन्हीं के भरोसे उच्च शिक्षा विभाग चल रहा है। ऑनलाइन काउंसलिंग के दौर में विभाग के पास कोई अलग से तकनीकी विशेषज्ञ भी नहीं है। ये प्रोफेसर ही ऑनलाइन काउंसलिंग करा रहे हैं।

एडमिशन की स्थिति खराब

प्रदेश के सरकारी और निजी कॉलेजों में इस बार एडमिशन की स्थिति बेहद खराब है। पहला मौका है, जब यूजी और पीजी में एडमिशन की संख्या कम नजर आ रही है। यूजी की 7 लाख 75 हजार सीटों में से 3 लाख 97 हजार सीटों पर ही एडमिशन हुए हैं। यूजी की अब भी 3 लाख 80 हजार सीटें खाली हैं। पीजी की 1 लाख 45 हजार सीटों में से 1 लाख सीटों पर एडमिशन हुए हैं।

रीवा के पूर्व और सिंगरौली के वर्तमान डीईओ बृजेश मिश्रा का निधन, फरीदाबाद में तोड़ा दम

शिक्षा जगह को बड़ा झटका, कुछ दिनों से चल रहे थे बीमार

जागरण, रीवा। शिक्षा विभाग के दबंग अधिकारियों में शुमार सिंगरौली के वर्तमान और रीवा के पूर्व डीईओ 55 वर्षीय बृजेश मिश्रा का गुरुवार को निधन हो गया। वह कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज फरीदाबाद दिल्ली के अस्पताल में चल रहा था। उनके निधन से शिक्षा जगत को गहरा झटका लगा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों और संगठन के पदाधिकारियों ने दुख व्यक्त किया है।

ज्ञात हो कि बृजेश मिश्रा रीवा में लंबे समय तक पदस्थ रहे। संयुक्त संचालक कार्यालय में भी रहे। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी का तीन मर्तबा प्रभार सम्हाला। दो मर्तबा रेग्युलर डीईओ भी रहे। बृजेश मिश्रा 4 अगस्त 2005 से 15 मई 2006, 11 अप्रैल 2010 से 28 अप्रैल 2010, 12 अगस्त 2014 से 6 जनवरी 2015 तक प्रभारी डीईओ रहे। इसके अलावा 7 जनवरी 2015 से 5 मार्च 2015 और 2 नवंबर 2016 से 26 जनवरी 2018 तक नियमित डीईओ रहे।

वे सीधी और सिंगरौली में भी जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में पदस्थ रहे। जेडी लोक शिक्षण संचालनालय की जिम्मेदारी भी सम्हाली। वर्तमान में वे सिंगरौली में ही पदस्थ थे। वहीं रहते हुए उनकी अचानक तबीयत खराब हुई थी। जिन्हें इलाज के लिए फरीदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उन्हें न्यूमोनिया की शिकायत होना बताया गया था। फेफड़े में इन्फेक्शन और किडनी ने काम करना बंद कर दिया था। डायलिसिस भी किया गया। कुछ दिनों से उनकी हालत खराब होने पर वेंटीलेटर पर रखा गया था। गुरुवार को उनकी अचानक इलाज के दौरान ही मौत हो गई। बृजेश मिश्रा के निधन से स्कूल शिक्षा जगत में शोक की लहर है। वह अपने पीछे पत्नी, एक बेटा, एक बेटी सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके निधन पर जिला शिक्षा अधिकारी डॉ आरएन पटेल और रमसा प्रभार डॉ पीएल मिश्रा ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उनका कहना है कि बृजेश मिश्रा के निधन से विभाग को भारी क्षति हुई है, जिसकी भरपाई मुश्किल है।

इन्होंने शोक संवेदनाएं व्यक्त की

सिंगरौली डीईओ बृजेश मिश्रा के निधन पर राज्य शिक्षक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनील तिवारी ने गहरा दुःख व्यक्त किया है। उनका कहना है कि श्री मिश्रा का निधन शिक्षा जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। इसके अलावा मप्र शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हर्षलाल शुक्ला, शिक्षक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आबाद खान, संभागीय अध्यक्ष बृजबिहारी मिश्रा, कार्यकारी जिला अध्यक्ष संजय तिवारी, महामंत्री शिवेन्द्र पाण्डेय, पंकज वाजपेई, प्राचार्य राजेंद्र सिंह बघेल, नरेन्द्र गौतम, संतोष शुक्ला, राजेश मिश्रा, गवर्नमेंट स्कूल कमांक दो के प्राचार्य राजेन्द्र मिश्रा, गिरीश मिश्रा आदि ने गहरा दुःख प्रकट किया है। इसके अलावा प्रो. एनडी बाजपेयी, डॉ केएस तिवारी, डॉ उमेश दीक्षित, डॉ एएन झा, विजय शंकर मिश्र, पूर्व जेडी अंजनी त्रिपाठी, संजय शुक्ल, प्राणनाथ पाण्डेय, यदुवंशमणि पाण्डेय, विजय कुमार पाण्डेय, संजय वाजपेयी, हरिवंश वाजपेयी, अवनीश शर्मा, उमेश पाण्डेय, नीरज पटेल भी ने गहरा शोक व्यक्त किया है।

एमबीए व एमसीए की च्वाइस फिलिंग प्रारंभ

कालेज लेवल काउंसलिंग 10 नवम्बर से

जागरण, रीवा। प्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में एमबीए तथा एमसीए पाठ्यक्रम के पहले चरण में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ है। विद्यार्थी इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन कर सकते हैं। यह च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया 28 अक्टूबर तक जारी रहेगी। दोनों पाठ्यक्रमों में पहले राउंड के तहत रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 24 अक्टूबर निर्धारित की गई है। सीट अलॉटमेंट एमबीए के छात्रों को पहले चरण में सीमेट 2020 की मेरिट के आधार पर अलॉटमेंट दिया जायेगा। रिक्त सीटों पर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यार्थियों के स्नातक परीक्षा के अंकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। इसके बाद रिक्त सीटों पर शैक्षणिक सत्र 20-19-20 के स्नातक अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित न होने के कारण पिछले दो वर्षों के अंकों की मेरिट के आधार पर प्रविधिक प्रवेश दिया जायेगा। एमसीए में पहले स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यार्थियों के परीक्षा के अंकों की मेरिट के आधार पर तथा रिक्त सीटों पर दो वर्षों के अंकों की मेरिट के आधार पर प्राविधिक दिया जायेगा। 10 नवम्बर से सीएलस्री एमबीए तथा एमसीए पाठ्यक्रम में 24 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी। च्वाइस फिलिंग 28 अक्टूबर तक, 25 एवं 26 अक्टूबर तक त्रुटि सुधार, 29 अक्टूबर को कॉमन मेरिट सूची जारी की जायेगी। इसी क्रम में 9 नवम्बर तक आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता, संस्था में उपस्थिति, मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया होगी। कालेज लेवल काउंसलिंग 10 से 13 नवम्बर तक होगी तथा 11 से 13 नवम्बर तक इच्छुक संस्था में प्रवेश के लिए उपस्थित होना होगा। प्राविधिक रूप से

प्रवेशित अभ्यर्थियों को संबंधित विश्वविद्यालय में पंजीयन से पूर्व अर्हताकारी परीक्षा के उत्तीर्ण परिणाम की अंकसूची प्रस्तुत कर एआईसीटीई द्वारा एमबीए पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित पात्रता सुनिश्चित करवाना अनिवार्य होगा अन्यथा उनका प्रवेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

आईटीआई में पंजीयन के लिए पोर्टल आज खुला रहेगा

रीवा। मौजूदा शिक्षण सत्र में आईटीआई, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में ओपन राउंड के लिए प्रवेश के लिये पोर्टल आज 16 अक्टूबर को रात्रि 12 बजे तक खुला रहेगा। आईटीआई में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र-छात्रायें इस अवधि में पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। आईटीआई में प्रवेश के लिये प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ चरण पूरे हो चुके हैं। ओपन राउंड के जरिए भी आईटीआई में प्रवेश के लिये रजिस्ट्रेशन व च्वाइस फिलिंग की जा सकती है। पूर्व में जिन आवेदकों को मैरिट के आधार पर आईटीआई में स्थान आवंटित हुआ था, अगर उन्होंने अभी तक प्रवेश नहीं लिया है तो उन्हें अब फिर से च्वाइस फिलिंग करनी होगी। च्वाइस फिलिंग न करने की दिशा में वे प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

शीघ्र रिजल्ट जारी करने की जद्दोजहद में विवि

पटरी से इतर एलएलबी दूसरे व चौथे सेम के मांग लिये ऑफलाइन अंक

जागरण, रीवा

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम की जद्दोजहद में जूझ रहा है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तय समय 15 अक्टूबर तक विश्वविद्यालय परिणाम जारी नहीं कर सका। अब विश्वविद्यालय ने एलएलबी द्वितीय व चौथे सेमेस्टर के असाइमेंट अंक ऑफलाइन मांग लिये हैं। ऑनलाइन अंक प्राप्त करने में होने वाली समस्या को देखते हुए विश्वविद्यालय ने पटरी से इतर कार्यवाही शुरू की है। विश्वविद्यालय ने संबंधित महाविद्यालयों को एलएलबी के अंक शीघ्र ऑफलाइन भेजने के लिए कहा है।

गौरतलब है कि सत्र 2019-20 की स्नातक अंतिम वर्ष व स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा ओपेन बुक प्रणाली के तहत गत माह करवाई। इन परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका अग्रणी महाविद्यालयों द्वारा जांची जा रही है, जो अभी तक मूल्यांकन कार्य पूरा नहीं कर पाये हैं। इधर, विभाग के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष का रिजल्ट सीसीई, प्रायोगिक व असाइमेंट के अंक के आधार पर तैयार कर रहा है। सभी छात्रों के अंक विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन ही महाविद्यालयों से मांगे हैं किंतु नियत समय तक सभी महाविद्यालय ऑनलाइन अंक नहीं दे सके। जैसे-तैसे उक्त कार्यवाही अब पूरी हो रही है। फिर भी एलएलबी दूसरे व चौथे सेमेस्टर के छात्रों के अंक विश्वविद्यालय तक नहीं पहुंच रहे थे, जिसके चलते विश्वविद्यालय ने उक्त निर्णय लिया है।

सस्ती तकनीकी व्यवस्था नहीं झेल पा रही छात्रों का बोझ

विश्वविद्यालय अब 20 अक्टूबर तक अधिकांश परीक्षा परिणाम जारी कर सकता है। विश्वविद्यालय के अधिकारी-कर्मचारी निरंतर इस बाबत कसरत कर रहे हैं। हालाकि तकनीकी दिक्कतों का सामना भी विश्वविद्यालय को करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय के तकनीकी अधिकारियों की बनाई तकनीकी व्यवस्था इतने छात्रों का बोझ नहीं झेल पा रही है। इस मामले की जांच के लिए तकनीकी पारंगत व्यक्ति का होना आवश्यक है परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस दिशा में कभी गम्भीरता से विचार नहीं किया। लिहाजा यदा-कदा ऐसी समस्या उत्पन्न होती रहती है।

बीई में प्रवेश के लिए आज अंतिम दिन

भोपाल। बैचलर आफ इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए पंजीयन कराने का शुक्रवार को अंतिम दिन रहेगा। करीब 55 हजार सीटों के लिए अब तक करीब साढ़े चार हजार पंजीयन हो चुके हैं। इसी तरह बैचलर आफ आर्किटेक्चर के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग शुक्रवार को कालेज का आवंटन जारी कर देगा। इसके बाद विद्यार्थी फीस जमा कर प्रवेश ले सकेंगे। (नप्र)

एमबीए में घटी विद्यार्थियों की रुचि, इसलिए कम हो रहे पंजीयन

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। तकनीकी शिक्षा विभाग ने एमबीए में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। काउंसिलिंग शुरू हुए तीन दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक एक हजार से भी कम विद्यार्थियों ने इस कोर्स में प्रवेश के लिए पंजीयन कराया है। यह तब है, जबकि पंजीयन कराने की अंतिम तारीख 24 अक्टूबर है। इसी तरह विद्यार्थियों की रुचि एमसीए में भी नहीं है। इसमें प्रवेश के लिए तीन दिन में पांच सौ से कम विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया।

यह पहले दौर की काउंसिलिंग है। इसके बाद कॉलेजस्तरीय काउंसिलिंग शुरू होगी। विद्यार्थियों को 15 से 28 अक्टूबर के बीच पसंद का कॉलेज चुनना होगा। 25 और 26 अक्टूबर को आवेदन में त्रुटि सुधार कराए जा सकेंगे। 29 को मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी। तीन नवंबर को कॉलेज का आवंटन कर दिया जाएगा। जिसके बाद नौ नवंबर तक आवंटित कॉलेज में विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लिया जा सकेगा।

ऐसे होगा सीटों का आवंटन : एमबीए में विद्यार्थियों को सीमेट की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। खाली सीटों पर स्नातक में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को अंतिम वर्ष के अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद खाली सीटों पर सत्र 2019-20 के स्नातक अंतिम वर्ष का रिजल्ट घोषित नहीं होने के कारण पिछले दो वर्षों के अंकों की मेरिट के आधार पर प्रावधिक प्रवेश दिया जाएगा। इसी तरह एमसीए में पहले स्नातक में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को और बाद में पिछले दो वर्षों के अंकों की मेरिट के आधार पर प्रावधिक प्रवेश दिया जाएगा।

नगर निगम के पूर्व कमिश्नर से बदसलूकी का आरोप

क्यों न रोक दें 2 वार्षिक वेतन वृद्धियां, प्राचार्य को नोटिस

भास्कर न्यूज | सतना

विधानसभा चुनाव के दौरान वर्ष 2018 में नगर निगम के तबके कमिश्नर प्रवीण सिंह अढ़ाइच से बदसलूकी के गंभीर मामले में रीवा संभाग के कमिश्नर राजेश जैन ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महुडर के प्रभारी प्राचार्य राजकुमार पांडेय को कारण बताओ नोटिस देकर जानना चाहा है कि क्यों न उनकी 2 वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोक दी जाएं? शोकॉज में जवाब के लिए 10दिन की मोहलत दी गई है। जवाब नहीं देने या फिर उत्तर समाधानकारक नहीं पाए जाने पर प्रभारी प्राचार्य को एक पक्षीय कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है।

ये हैं आरोप

प्रकरण के मुताबिक वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान यहां बगहा हाईस्कूल स्थित मतदान केंद्र क्रमांक- 55 में प्रभारी प्राचार्य राजकुमार पांडेय बतौर पीठासीन अधिकारी नियुक्त थे। आरोप है कि तबके निगमायुक्त प्रवीण सिंह अढ़ाइच जब मतदान केंद्र के निरीक्षण के लिए पहुंचे तो उनके साथ अभद्रता की गई। इतना ही नहीं मतदाताओं को अपनी पहचान के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित पहचान पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में भी राजकुमार पांडेय ने मतदाताओं से भी अभद्रता की। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर ने प्रभारी प्राचार्य के इस कृत्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत रीवा संभाग के कमिश्नर को प्रतिवेदन भेजा था।

जनवरी 2021 से केंद्र कराएगा पहली श्रमगणना

डॉक्टर, वकील, मजदूर माली; अब सबकी गणना

कोरोनाकाल से केंद्र सरकार ने लिया सबक

तब... सरकार संसद में नहीं बता पाई थी लॉकडाउन में काम छोड़ घर लौटे प्रवासी मजदूरों की संख्या

अब... जिला स्तर पर मजदूरों का ही नहीं हर पेशेवर का ब्योरा रखेंगे, सर्वे के लिए तैयार हो रही है नीति

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

कोरोनाकाल में देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान लगभग हर बड़े शहर से लाखों मजदूरों के पलायन की तस्वीरें तो पूरे देश ने देखी...मगर इनकी सही संख्या कितनी थी, किस राज्य से कितने मजदूर कहां गए और उनमें से कितने काम पर लौटे...यह आंकड़ा किसी के पास नहीं है। यहां तक कि केंद्र सरकार संसद में भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई।

मगर कोरोनाकाल के इस सबक ने सरकार को भविष्य के लिए तैयार कर दिया है। अब पहली बार केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने देशव्यापी 'श्रमगणना' की तैयारी कर ली है। इसके तहत मंत्रालय के अधीन काम करने वाला लेबर ब्यूरो पूरे देश में हर पेशे से जुड़े व्यक्ति की गणना करेगा। यानी पूरे देश में कितने वकील, डॉक्टर-इंजीनियर, सीए ही नहीं कितने मजदूर, माली, कुक और ड्राइवर तक हैं...पूरी गणना की जाएगी। अभी यह गिनती हर छह माह और भविष्य में हर तीन माह में की जाएगी। शेष पेज 10 पर

अभी हर 6 माह में की जाएगी गणना

कमेटी के सदस्य सह श्रम ब्यूरो के महानिदेशक डीपीएस नेगी ने बताया कि गणना वैज्ञानिक सर्वे के आधार पर की जाएगी। सर्वे के तरीके पर अगले 6 दिन में स्पष्ट नीति बनेगी। सर्वे में जिला स्तर पर फैक्ट्री, दफ्तर, हॉस्पिटल और आरडब्ल्यूए जैसे इंस्टीट्यूशन्स से पेशवरों का आंकड़ा लिया जाएगा। साथ ही हर जिले में सीमित हाउसहोल्ड सर्वे भी किए जा सकते हैं।

- आंकड़ा जिला स्तर, राज्य स्तर और फिर केन्द्रीय स्तर पर तैयार होगा। सर्वे टीम की ट्रेनिंग अगले दो माह में पूरी होने की उम्मीद है।
- लेबर ब्यूरो के अधिकारियों व कर्मचारियों के अलावा सर्वे के लिए अनुबंध पर भर्तियां होंगी।
- जनवरी-2021 से सर्वे की शुरुआत हो सकती है। 6 माह में सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा।

श्रमगणना पर सबसे जरूरी 3 सवाल

सर्वे की जरूरत क्यों : राज्य कामगारों-पेशवरों की सूचना नहीं देते या देने में देरी करते हैं। अब कानून में बदलाव करके लेबर ब्यूरो को इसके लिए पूरी तरह से शक्ति दे दी गई है।

जानकारी कैसी रखेंगे : डॉक्टर-इंजीनियर से घरेलू नौकर-माली तक हर पेशे में कितने लोग हैं। यह कितनी देर काम करते हैं और इसके बदले कितना पैसा मिलता है।

इसका फायदा क्या : सभी पेशेवरों को सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क से जोड़ेंगे। आंकड़ों के आधार पर नीतियों में अपेक्षित परिवर्तन होंगे। कामगारों के वेतन पर भी विचार होगा।

आईयूएमएसी से स्टूडेंट के डेटा लीक होने का खतरा

हरिभूमि न्यूज ▶▶| भोपाल

प्रदेश में सभी 21 शासकीय विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली को डिजिटल मोड, ऑटोमेशन में लाने के उददेश्य से एकीकृत विवि प्रबंधन प्रणाली (आईयूएमएसी) लागू की जा रही है।

आईयूएमएस को बिना किसी प्लानिंग व विचार-विमर्श के लागू करने से शिक्षा के साथ अन्याय तो होगा। वहीं इससे स्टूडेंट्स के डेटा लीक होने के खतरे के साथ विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता पर ब्रेक लग जाएगा। यह बात मीडिया से चर्चा करते हुए अभाविप के प्रदेश मंत्री निलेश सोलंकी ने कही। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही इस प्रणाली को निरस्त नहीं किया गया तो एबीवीपी सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि आईयूएमएस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की इस मूल भावना के विपरीत है।

आयोजनों में दिखा कोरोना संक्रमण का असर

स्कूलों में धुल गया 'विश्व हाथ धुलाई दिवस', शहर के शासकीय स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति रही कम

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

गुरुवार को राजधानी के लगभग सभी स्कूलों में विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया गया। हालांकि इस बार स्कूलों में पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों हाथ धुलाई अभियान में शामिल नहीं हो सके। जिसके चलते बीते वर्षों के मुकाबले स्कूलों में इस बार विश्व हाथ धुलाई दिवस खुद ही धुल गया। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के गिने-चुने विद्यार्थी ही स्कूल में पहुंचे। जिन्हें शिक्षकों ने हाथ धुलाई के महत्व समझाया। बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते फिलहाल प्रदेश में पहली से आठवीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल नहीं खोले गए हैं, वहीं 9 से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए आंशिक रूप से स्कूल खोले जा रहे हैं। यह विद्यार्थी भी अभिभावकों से अनुमति के बाद ही कुछ समय के लिए स्कूल आ सकते हैं। ऐसे में फिलहाल स्कूलों में बहुत की कम संख्या में विद्यार्थी पहुंच रहे हैं।

शासकीय कमला नेहरू उमा विद्यालय में बच्चे हाथ धोते हुए

कुछ स्कूलों में नहीं की गई कोई व्यवस्था

कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में चल रहे हाई अलर्ट के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने बच्चों को इस संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता के साथ सावधानियां बरतने के निर्देश दिए हैं, लेकिन विभाग के आदेश पहले दिन ही राजधानी के कई स्कूलों में बेअसर रहे। कुछ स्कूल ऐसे भी थे जहां प्रबंधन का कहना था कि जब बच्चे ही स्कूल नहीं आ रहे हैं तो हाथ धुलाई किसको कराएं।

कंप्यूटर साइंस ब्रांच की सबसे अधिक डिमांड

भोपाल। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा बीई के लिए ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया जारी है। इस बार प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा साइंस आदि क्षेत्रों में नई ब्रांच में एडमिशन दिए जा रहे हैं। इनमें स्टूडेंट्स रुचि भी ले रहे हैं। वहीं सत्र 2020-21 में स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग (सीएसई) ब्रांच से इंजीनियरिंग करने के लिए छात्र-छात्राओं का अधिक रुझान है। विभाग के अनुसार इस बार अलग-अलग कॉलेजों में सीएसई में एडमिशन के लिए 1 लाख 50 हजार 495 बार च्वाइस लॉक की गई है। जो कि अन्य ब्रांच की तुलना में तीन गुना अधिक है। वहीं सिविल इंजीनियरिंग से अधिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन, इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी में अधिक रुझान है।

बीयू की सीटें खाली, अब पहले आओ पहले पाओ एडमिशन

भोपाल। बरकतउल्ला यूनिविर्सिटी में प्रमुख कोर्स को छोड़ दिया जाए तो कई कोर्स में 100 प्रतिशत तक सीटें खाली हैं। यहां एक माह से भी अधिक समय में सभी कोर्स को मिलाकर भी एक हजार एडमिशन नहीं हुए हैं। कुछ कोर्स में तो प्रवेश का खाता भी नहीं खुला है, वहीं कई में नाम मात्र को ही प्रवेश हुए हैं। बीयू गुरुवार से खाली सीटों को भरने के लिए पहले आओ, पहले पाओ के तहत प्रवेश देगा। जिसके अनुसार जो भी छात्र पहले आवेदन कर के पहले फीस जमा कर देगा, उसे खाली सीट होने पर एडमिशन मिल जाएगा। बीयू द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक यहां संचालित होने वाले विभिन्न कोर्स की 1300 सीटों पर इस साल एडमिशन होना है ।विवि के महिला अध्ययन विभाग में संचालित दोनों कोर्स में अभी तक एक भी एडमिशन नहीं हुआ है। एमए वुमन स्टडीज में 20 सीट के लिए सिर्फ दो आवेदन आए हैं, जिसमें से एक ने भी एडमिशन नहीं लिया है।

प्रवेश की स्थिति: एमए अरबी में 2, डिप्लोमा इन मॉडर्न अरेबिक लैंग्वेज में 9, सर्टिफिकेट मॉडर्न अरेबिक लैंग्वेज में 24 सीट खाली हैं। एमए लैग्वेस्टिक में 10, एमए संस्कृत में 8, एमए हिंदी में 10, एमए उर्दू में 20, एमए पर्सियन में 4 और एमए एजुकेशन में 10 सीट खाली हैं। पीजी डिप्लोमा योग थैरेपी में 27, पीजी डिप्लोमा स्ट्रेस मैनेजमेंट में 18 सीट खाली हैं। यूआईटी में संचालित एमएससी केमिस्ट्री में 4, एमएससी मैथस में 9 और सर्टिफिकेट इको सिस्टम में 20 सीट खाली हैं।

विश्व छात्र दिवस विशेषः अधिकांश बच्चों के पास नहीं है मोबाइल

कोरोना की मार से नहीं खुल सके स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चे हुए शिक्षा से दूर

पीपुल्स संवाददाता ● चंदेरा
मो.नं. 8962420210

फाइल फोटो

भले ही लोक डाउन पूरी तरह अनलॉक कर दिया गया हो, लेकिन जिले सहित प्रदेश में स्कूल खोलने की कोई मजबूत रणनीति फिलहाल नजर नहीं आ रही है। प्राइमरी के बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस भी शासन स्तर पर बंद करवा दी गई है। अन्य बच्चों को दूरदर्शन पर पढ़ाई करवाई जा रही है। तो वही आने वाले दिनों में स्कूल खुलेंगे या नहीं इसके लिए सरकारी स्कूलों में कोई तैयारी फिलहाल नहीं की गई है। जुलाई महीने से संचालित होने बाले स्कूलो को नवम्बर तक आंरभ न किया जा सका। क्योकि कोरोना संक्रमण की बजह से शासन ने तमाम स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिये हैं। जिससे बच्चों की पढ़ाई का शेड्यूल गड़बड़ा गया है। शिक्षक भी बच्चो की पढ़ाई और शाला खुलने को लेकर कुछ कहने में असमर्थ है।

जिले भर का यदि आंकड़ा निकाला जाए तो सामने आता है कि ज्यादातर बच्चे निजी शालाओ में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। वही शासकीय शिक्षक भी अपने नॉनिहालो को निजी संस्थानों में ही पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं। जिसके पीछे की सबसे बड़ी बजह सरकारी शिक्षा के प्रति अविश्वास है। इसी कारण आधुनिक सुबिधाओं से लेस बच्चो पर लॉक डाउन और फ्री समय का कुछ खास असर नहीं हुआ, लेकिन जरूरत मन्दों की पहुंच से ऑनलाइन व्यवस्था कोसो दूर है। निजी और सरकारी स्कूल में इस समय दावा किया जा रहा है कि मोबाइल कम्प्यूटर लेपटॉप के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है, लेकिन अधिकांश बच्चो के पास तो मोबाइल हीं नहीं है। ऐसे में उन्हें कैसे पढ़ाई कराई जाए, कैसे स्कूल खुले बिना उनकी पढ़ाई होगी जैसी तमाम चुनोतियां शिक्षा विभाग के सामने फिलहाल बनी हुई है।

ठप्प पड़ी सुविधाएं

देश में वैश्विक महामारी कोविड19 के कारण अभी सभी शालाए बंद है ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के पढ़ाई की भरपाई एवं व्यक्तित्व विकास के लिए शासन द्वारा छात्र छात्राओ के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था टीवी मोबाइल रेडियो दूरदर्शन के माध्यम से आरम्भ की गई है जिसके लिए शासन ने डिजीलेब पोर्टल भी शुरू किया है। जिसमें दूरस्थ अंचलो में रहने वाले बच्चे भी शिक्षा से वंचित नही रहेंगे। जिसमें प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, संकुल नोडल अधिकारियों को विकास खंड स्तरों पर तकनीकी प्रशिक्षण दिया था। प्रशिक्षण के बाद कई स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू भी कर दी गई। किन्तु सुविधाएं पूरी तरह से ठप्प है।

नेटवर्क बड़ी समस्याः जानकारी के अनुसार पलेरा विकास खंड अंतर्गत लगभग 32000 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। जिसमे से 50 प्रतिशत बच्चे ही ऑनलाइन क्लास का लाभ ले पा रहे हैं। इसमें30 प्रतिशत मोबाइल, 10 प्रतिशत टीवी ,एवं10 प्रतिशत रेडियो से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वही 50 प्रतिशत बच्चो के पास ऑनलाइन पढ़ाई का कोई साधन उपलब्ध न होने से शिक्षा से दूरी बनाए हुए हैं। वही जतारा विकास खंड के संचालित स्कूलों में अध्ययन करने वाले लगभग 22000 बच्चो में से 30से 35 प्रतिशत बच्चे ही ऑनलाइन कक्षाओं के लाभ ले सके। बाकी किसी के पास मोबाइल फोन नही है, तो कई को नेटवर्क की समस्या है।

केस नंबर-1

कक्षा 10वी में पढ़ने बाली दीपा ने बताया कि उसके यहाँ न तो टीवी है और नही एंड्रॉयड मोबाइल जिससे वह पढ़ाई का लाभ ले सके। इस संबंध में पिता पप्पू चैरसिया बताते हैं कि घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण दो जून की रोटी की जुगाड़ करना कठिन होता है तो बेटी की पढ़ाई के लिए कैसे मोबाइल फोन टीवी खरीदे।

केस नम्बर 2-

वही कक्षा 8वी में पढ़ने बाली रौनक का कहना है कि जब से स्कूल बंद हुए हैं तब से पढ़ाई चैपट हो गई है। घर पर कोई ऐसा साधन नही है जिससे ऑनलाइन स्टडी की जा सके। जिसके संबंध में पिता कालका प्रसाद कहते हैं बच्चो की पढ़ाई लॉक डाउन के कारण खत्म है। साधन न होने से फिलहाल बच्चो ने पढ़ाई से दूरी बना ली है।

केस नम्बर -3

वही छात्र अभिषेक विश्वकर्मा का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए साधन उपलब्ध नहीं है। जिसकारण वह अन्य विद्यार्थियों से पिछड़ गया है। घर की आमदनी सीमित खर्च ज्यादा होने से उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वह मोबाइल टीवी ले सके।

बीयू : कोर्सवर्क एग्जाम 20 से 22 तक, एडमिट कार्ड कल होंगे जारी

भोपाल। बरकतउल्ला विवि (बीयू) द्वारा पीएचडी एंट्रेस एग्जाम में पास हुए करीब 900 स्टूडेंट्स के कासेवर्क एग्जाम 20 से 22 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। इसमें शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड 17 अक्टूबर को जारी होंगे। स्टूडेंट्स को घर बैठकर ही परीक्षा देनी है। इसलिए रोल नंबर के आधार पर ही रिजल्ट तैयार किए जाएंगे।

बीयू 20 से 22 अक्टूबर तक सुबह साढ़े सात बजे पेपर को वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। सभी प्रश्नों के उत्तर देने के बाद स्टूडेंट्स 2 बजे तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से उसे बीयू भेजेंगे। स्पीड पोस्ट की रसीद एचओडी को वाट्सऐप करना होगा। दो बजे के बाद विवि कॉपी स्वीकृत नहीं करेगा। स्थानीय स्टूडेंट्स को बीयू पहुंचकर कॉपी जमा करना अनिवार्य है। स्टूडेंट्स 20 पेज की कॉपी तैयार करेंगे। इसमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 400 शब्दों में लिखना है। एग्जाम में करीब 900 स्टूडेंट्स शामिल होंगे।

रिजल्ट घोषित नहीं, तो यूजी-पीजी में मिलेगा अस्थाई प्रवेश

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने दी सुविधा

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल

मो.नं. 9893231237

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विवि (इग्नू) में इस साल यूजी और पीजी कोर्स के लिए उन स्टूडेंट्स के एडमिशन हो सकेंगे, जिनका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है या फिर उन्हें मार्कशीट नहीं मिली है। इग्नू में एडमिशन तो मिल जाएगा, लेकिन अस्थाई होगा। कोविड-19 के कारण जुलाई 2020 सत्र में प्रवेश के लिए यह सुविधा मिल रही है।

इग्नू ने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण लगभग सभी शैक्षणिक संस्थानों का रिजल्ट प्रभावित हुआ है। रिजल्ट और अंकसूची की कमी से जूझते स्टूडेंट्स को इग्नू ने अपने जुलाई के शैक्षणिक सत्र के लिए यूजी व पीजी कोर्स में दाखिले के लिए अस्थाई प्रवेश की यह सुविधा दी है। इग्नू में एडमिशन के लिए परीक्षा में शामिल होने का सर्टिफिकेट देना होगा। इसके तहत स्टूडेंट्स को कुछ मानकों का पालन करना होगा। स्टूडेंट्स इग्नू के यूजी कोर्स में प्रवेश चाहते हैं, तो 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने का प्रमाण पत्र देना होगा। वहीं, पीजी के लिए ग्रेजुएशन सेकंड ईयर या पांचवें सेमेस्टर का पास सर्टिफिकेट देना होगा। इग्नू में अस्थाई प्रवेश पाने वाले स्टूडेंट्स को वास्तविक व मूल प्रमाण पत्र, अंकसूची जमा करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय मिलेगा। इस समय तक जरूरी दस्तावेज जमा न करने पर प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। इग्नू के अनुसार, अस्थाई प्रवेश पाने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। वहीं, विवि ने दिसंबर टर्म एंड परीक्षा के लिए असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी है। अब स्टूडेंट्स 31 अक्टूबर तक असाइनमेंट जमा कर सकते हैं।

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विज्ञान एवं वाणिज्य
महाविद्यालय, राजहर्ष कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल म.प्र.
फोन नं. 0755-2551837, E-mail : hegbsccbho@mp.gov.in
www.mp.gov.in/highereducation/benazircollege

क्रमांक/907/शा.डॉ. श्या.प्र.मु.महा./2020 भोपाल, दिनांक 12/10/2020

प्रेस विज्ञाप्ति

शासकीय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल म.प्र. जो पूर्व में गोखले छात्रावास, जहाँगीराबाद भोपाल में संचालित हो रहा था वह अब वर्तमान में अपने नवीन भवन, राजहर्ष कॉलोनी, कोलार रोड में स्थानांतरित हो चुका है, तथा महाविद्यालय का नाम तथा पता "शासकीय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, राजहर्ष कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल म.प्र." हो गया है।

विद्यार्थियों के प्रवेश, सत्यापन आदि संबंधित सभी कार्य नवीन भवन से ही संचालित हो रहे है। महाविद्यालय में वर्तमान में कला संकाय, वाणिज्य संकाय, विज्ञान संकाय एवं गृहविज्ञान संकाय स्नातक स्तर पर एवं वाणिज्य संकाय, कला संकाय में समाजशास्त्र, इतिहास एवं विज्ञान संकाय में गणित, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र में स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम संचालित है, जो विद्यार्थी उपरोक्त संकाय में प्रवेश लेना चाहते है वो म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से महाविद्यालय में प्रवेश ले सकते है।

(डॉ. सरोज श्रीवास्तव)
प्राचार्य
शास. श्यामा प्रसाद मुखर्जी
विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल

G-14907/20